>

Title: Need to provide electricity connections under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in villages of Deoria parliamentary constituency, Uttar Pradesh.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई । इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मजरो के विद्युतीकरण के लिए धनराशि की मांग की थी । उस समय केंद्र सरकार ने कहा कि सभी प्रदेशों में सभी गांवों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाये तो मजरो के विद्युतीकरण किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी । कई राज्यों में मजरो की विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे दी है परंतु उत्तर प्रदेश को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है । जबकि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं । वर्ष 2009 को 1,37,060 मजरो के विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने दिया परंतु केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को छोड़कर किसी और जनपद हेतु यह स्वीकृति नहीं दी है । इन सबके कारण अनुसूचित जाति के कई हजार गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहूंची है । ट्रंसफार्मर बन गये हैं परंतु उन पर से कनेक्शन नहीं दिये गये हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र के लार इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है । जहां पर दलित बस्तियां है जिनकी वजह से यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है । कई जगहों पर खंभे लग गये हैं परंतु उन पर तार नहीं बिछाये गये हैं ।

सरकार से अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समुचित ढंग से समय पर क्रियान्वयन के लिए प्रयास किये जाये ।